

taking steps to send out our technical team or teams to Soviet Russia for the purpose the hon. Member has mentioned.

Shri N. B. Chowdhury: May I know whether we can have an idea of the time when the work will start?

Shri K. C. Reddy: The time is specifically mentioned in the agreement.

COMPETENT OFFICERS

*246. **Sardar Akarpuri:** Will the Minister of Rehabilitation be pleased to state whether it is a fact that Government propose to abolish the posts of Competent Officers and entrust their duties to Revenue Officers in Tehsils?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले): जी नहीं।

सरदार अकरपुरी: क्या मैं जान सकता हूँ कि आया काम्पिटेंट आफिसर्स का काम तसल्ली बस्था है, और वह कब तक खत्म होगा ?

श्री जे० के० भोंसले: काम तो बहुत तसल्ली बस्था है, लेकिन कब तक खत्म होगा यह नहीं बतलाया जा सकता।

सरदार अकरपुरी: पंजाब में हजारों रिफ्यूजीज को जमीन नहीं मिली है। काम्पिटेंट आफिसर्स ने जमीन खाली कराकर उनको दी है। तो क्या मैं जान सकता हूँ कि सरकार उनके यह काम तेजी से खत्म करने की ताकदी करेगी ?

श्री जे० के० भोंसले: माननीय सदस्य को यह नहीं मालूम है कि इसमें काम्पिटेंट आफिसर्स का सवाल नहीं है। काम्पिटेंट आफिसर्स इसलिए हैं कि जो कम्पोजिट प्रॉपर्टी है उसका डिवीजन करें, यानी इक्वैली के इंटरेस्ट को अलग करें और क्लॉमेट के विवाद को अलग करें। लेकिन जहाँ तक जमीन देने का सवाल है, वह तो रवेन्यू आफिसर्स का काम है।

सरदार अकरपुरी: मैं तो तजर्ब की बिना पर कहता हूँ। आप शायद रिकार्ड की बिना पर कहते हैं। जो वहाँ होता है वह यह कि नोटिस देकर जमीन खाली करवाई जाती है और उसको नीलाम कर दिया जाता है। तो जमीन एलाट करने का काम तो रवेन्यू आफिसर्स का है और वे उसको करेंगे, लेकिन खाली तो वह करायेंगे। इस लिए मैं ने कहा कि क्या सरकार उनसे जल्दी जमीन खाली कराने के लिए ताकदी करेगी।

Mr. Speaker: The point is, it is true that the Revenue Officers allot the land which is vacated. But, the duty of vacating the land is that of the Competent Officers. Have Government considered that point of view to expedite the work of vacating the property so that it can be allotted by the Revenue Officers?

श्री जे० के० भोंसले: अगर वह सेपरेशन का काम है, तो काम्पिटेंट आफिसर्स जरूर करेंगे।

EXPORT OF HUSKED RICE

*247. **Shri Sadhan Gupta:** Will the Minister of Commerce and Industry be pleased to state the reasons for liberalising the export of husked rice and for the reduction of the export duty thereon?

The Deputy Minister of Commerce and Industry (Shri Kanungo): With the return to normal conditions, the pre-war pattern of trade was allowed to be re-established. In the pre-war period India was both an exporter and importer of rice.

The export duty was imposed when there was a wide margin between internal and external prices. With the fall in world prices, the duty of 20 per cent *ad valorem* could not be sustained and had to be reduced to the pre-war level of 2 annas 3 pies per maund.

Shri Sadhan Gupta: May I know whether this liberalisation of export